



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 224 ]  
No. 224]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 1997/अग्रहायण 3, 1919  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 1997/AGRAHAYANA 3, 1919

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1997

संख्या पी-20012/29/97-पी. पी.—पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की वर्तमान प्रणाली तेल गूल्य समिति, 1976 की सिफारिशों पर आधारित है जिन्हें भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 16 दिसंबर, 1977 के संकल्प संख्या पी-20028/3/77-पीपीडी (संड II) के अंतर्गत अनुमोदित किया गया और जिनमें भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल लागत समीक्षा समिति, 1984 की सिफारिशों के आधार पर अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 के आदेश संख्या पी-20012/48/84-पीपी के तहत संशोधन किया गया। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत प्रतिधारण संकल्पना के आधार पर तेल रिफाइनरियों, विपणन कंपनियों और पाइपलाइनों की क्षतिपूर्ति की जाती है और नेटवर्थ पर 12% कर पश्चात् प्रतिलाभ दिया जाता है। स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य भी लागत जमा सूत्र पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल उत्पादक कंपनियों की प्रचालन लागत और 15% कर पश्चात् प्रतिलाभ दिया जाता है।

2. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 1995 के आदेश संख्या पी-20029/21/94-पीपी के अंतर्गत तेल उद्योग के पुनर्गठन के लिए आवश्यक नीतिगत उद्देश्यों और पहलों को पूरा करने हेतु सिफारिशों देने के लिए तेल उद्योग के पुनर्गठन संबंधी कार्यनीतिक योजना दल

(आर ग्रुप) का गठन किया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रशासन, प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल थे। 'आर' ग्रुप ने प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को क्रमिक रूप से चरणों में समाप्त करने और मुक्त विपणन व्यवस्था का आरंभ करने की सिफारिश की थी। सरकार ने 1.9.97 को 'आर' ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर घरणबद्ध ढंग से सुधारों की शुरुआत करने के द्वारा प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया था।

3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 25 जून, 1996 के आदेश संख्या पी-20029/21/95-पीपी के अंतर्गत प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में शुल्क संरचना के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ तकनीकी दल की भी नियुक्ति की थी। विशेषज्ञ तकनीकी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के पास विद्यारथीन थी। इस रिपोर्ट में चरणबद्ध ढंग से बाजार निर्धारित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था अपनाने और प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर दिए जाने के संबंध में सीमाप्रशुल्क और उत्पाद-शुल्क दरों तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

4. भारत सरकार ने विशेषज्ञ तकनीकी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को चरणों में समाप्त करने और अंतिम वर्ष अर्थात् 2001-02 के लिए शुल्क संरचना के बचौरे के संबंध में निर्णय कर लिया है। छ्यौरा नीचे दिया गया है :

- क. 1998-99 से आरंभ करते हुए अनुबंध-I में दिए गए क्रम के अनुसार चरणों में पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करना।
- ख. स्वदेशी कच्चे तेल उत्पादकों के लिए लागत जमा सूत्र वापिस लियो जाता है और संक्रमण अवधि के दौरान कच्चे तेल के वास्तविक आयात के भारित औसत पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पूर्व-घोषित बढ़े हुए प्रतिशत का भुगतान करते हुए चरणबद्ध ढंग से तेल उत्पादकों को प्राप्य मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तरों तक बढ़ाया जाएगा।
- ग. सभी (विद्यमान और नई) रिफाइनरियों के लिए प्रतिधारण मूल्य निर्धारण की प्रणाली समाप्त की जाती है और रिफाइनरी द्वारा स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण आयात समानता की ओर अग्रसर होगा, लेकिन नियंत्रित उत्पादों अर्थात् एम एस, एचएसडी, एसकेओ, एलपीजी और एटीएफ के रिफाइनरी द्वारा मूल्य संक्रमण अवधि के दौरान विद्यमान रिफाइनरियों के लिए 'समायोजित आयात समानता' पर नियत किए जाएंगे, रिफाइनरियों द्वारा सुभी अन्य उत्पाद बाजार आधारित मूल्यों पर बेचे जाएंगे।
- घ. मुहुर पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य बाजार मूल्यों की ओर अग्रसर किए जाएंगे, एचएसडी का मूल्य भंडारण-स्थित स्तर तक तत्काल प्रभाव से आयात समानता मूल्य-निर्धारण के सिद्धांत पर नियत किया जाएगा और अन्य मुहुर उत्पादों अर्थात् एलपीजी, एटीएफ, एसकेओ और एमएस के मूल्य चरणबद्ध ढंग से आयात समानता के सिद्धांत की ओर अग्रसर किए जाएंगे और

पैराफिन-मोम, बिटुमेन, नाफ्था, एफओ और एलएसएचएस का मूल्य-निर्धारण नियंत्रणमुक्त कर दिया जाएगा।

- इ. संक्रमण अवधि का उपयोग लगभग 18,200 करोड़ रुपए मूल्य के उन तेल बांडों की सर्विसिंग और परिशोधन के लिए किया जाएगा, जो सरकार द्वारा तेल कंपनियों को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, उपर्युक्त कूड़ और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य तेल समन्वय समिति द्वारा बढ़ी हुई स्थापत्त शक्तियों के साथ नियत किया जाएगा।
- इ. संक्रमण अवधि के दौरान कूड़ (स्लॉप कूड़ और कैडेनसेट), एनजीएल, एटीएफ, एमएस और एथएसडी के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों का आपात और निर्धारित नियंत्रणमुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन संयुक्त और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को वास्तविक प्रयोक्ता लाहसेसिंग नीति के अंतर्गत कूड़ के श्रोतीकरण और आपात की अनुमति दी जाएगी।
- छ. कूड़ और पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों को घरणबद्ध ढंग से तर्कसंमत किया जाएगा।
- ज. उचित प्रशुल्क संरक्षण और कम से कम 2000 करोड़ रुपए के निवेश सहित रिफाइनरियों के स्वामित्व और प्रचालन पर एमएस, एथएसडी और एटीएफ जैसे परिवहन ईंधनों के लिए विषयन अधिकारों को सशर्त बनाकर या तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों द्वारा वार्षिक रूप से कम से कम 3 मिलियन टन कथ्ये तेल का उत्पादन करने पर शोधन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- झ. कथ्ये तेल के प्रेषण के लिए लागत-जमा सूत्र वापिस लिया जाता है और दरे बाजार संबंधित दरों की ओर अग्रसर होंगी।
- ठ. दूरवर्ती क्षेत्रों को अपूर्ति पर भाइ-राजभाष्यता राजकोषीय बजट के माध्यम से पूरी की जाएगी और :
- ठ. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के क्रियाकलापों और प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धात्मक ढाँचे की निगरानी करने के लिए एक नियंत्रक ढाँचे की स्थापना।
- ५. हसमें उल्लिखित निर्णय 1.4.1998 के बाद से लागू होंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, लोकसभा और राज्य सभा साधेवालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

## सुधारों का चरणबद्ध कार्यक्रम

विवरण

अंतरण चरण

वर्ष-1 (1998-1999)

मॉडल

4 वर्ष

(i) कॉस्ट एस फार्मूला समाप्त करना और क्रूड उत्पादकों को आस्तीक आयात के पोत पर्यन्त भाड़ा कीमत के भारित औसत के रूप में भुगतान।

(ii) अंतरण अवधि के दौरान नियंत्रित रखे जाने वाले उत्पाद।

(iii) रिफाइनरियों के लिए रिटेंशन मार्जिन संधारणा और नियंत्रित उत्पादों के लिए रिफाइनरी कीमतों की वापसी।

(iv) डीकंट्रोल किए जाने वाले उत्पाद।

(v) एक्जिन नीति।

75 प्रतिशत

एम एस, एच एस डी, केरोसिन, ए टी एफ और एल पी जी।

वर्तमान रिफाइनरियों को समायोजित आयात समतुल्य कीमतें तथा नई रिफाइनरियों को टैरिफ समायोजित आयात समतुल्य कीमतें।

नेप्या, एफ जी, एल एस एच एस, बिटुमिन पेराफिन वैक्स।

क्रूड (स्लाप क्रूड और क्रूड कंडन्सेड) एन जी एल, ए टी एफ, एम एस और एच एस डी को छोड़ कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात का डीकेमालाइजेशन।

क्रूड की उपस्थिता का उदारीकरण और संयुक्त तथा निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस के अंतर्गत आयात की अनुमति।

चरणबद्ध तरीके से युक्तोक्तम्।

(vi) क्रूड की उपलब्धता

(vii) सीमा-शुल्क

(viii) निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि केरोसिन (पी. डी. एस.)

एल पी जी (घरेलू)।

(ix) भाड़ा और अन्य अंडर-रिकवरिज़।

(x) कच्चे तेल का नौवहन।

वर्तमान भंडारण प्वाइंट का 30 प्रतिशत।

पास की जाने वाली सब्सिडी का 33 प्रतिशत।

33 प्रतिशत समान रूप से पास किया जाएगा।

कच्चे तेल के लिए कॉस्ट एस फार्मूला को वापस लेना और संबद्ध आजार दरों की ओर जाना।

वर्ष-2 (1999-2000)

(i) पोतपर्यन्त भाड़े भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान।

77.5 प्रतिशत।

(ii) निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि केरोसिन (पी. डी. एस.)

एक वर्ष के अंत तक संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 30 प्रतिशत।

एल पी जी (घरेलू)।

33 प्रतिशत की और सब्सिडी पास की जाए।

(iii) भाड़ा और अन्य अंडर-रिकवरिज़।

33 प्रतिशत समान रूप से पास किया जाएगा।

(iv) शुल्कों का युक्तीकरण।

जारी रखा जाए।

वर्ष-3 (2000-2001)

(i) पोतपर्यन्त भाड़ा कीमत की भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान।

80 प्रतिशत।

(ii) ए टी एफ।

आयातों और कीमत निर्धारण डी-रेगुलेशन।

(iii) निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि केरोसिन (पी. डी. एस.)।

वर्ष के आरम्भ में संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 20 प्रतिशत।

एल पी जी (घरेलू)।

आयात समानता में 15 प्रतिशत सब्सिडी स्तर तक पहुँचने के लिए कीमतों

(iv) भाड़ा और अन्य अंडर-रिकवरिज़।

में उपयुक्त समायोजन।

बकाया सब्सिडी को समान रूप से पास किया जाए।

वर्ष-4 (2001-2002)

(i) पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में भारित ओसत के प्रतिशत के रूप में क्रूड उत्पादकों को भुगतान। 82.5 प्रतिशत।

(ii) निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि केरेसिन (पी. डी. एस.)। आयात समानता में 33.33 प्रतिशत सब्सिडी स्तर तक पहुँचने के लिए कीमतों में उपयुक्त समायोजन।  
पूर्ण विनियंत्रण  
सरकार के राजकोषीय बजट में एस के ओ, पी डी एस, एल पी जी (घोरेलू) की सब्सिडी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में आपूर्तियों पर भाड़ा सब्सिडी का अंतरण।

2002 से आगे

**MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS****RESOLUTION**

New Delhi, the 21st November, 1997

**NO.P-20012/29/97-PP** — The existing system of pricing of petroleum products is based on the recommendations of Oil Prices Committee, 1976 as approved by the Government of India, Ministry of Petroleum vide its Resolution No P-20028/3/77-PPD (Vol II) dated December 16, 1977 and as amended by the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide order No P-20012/48/84-PP dated October 23, 1986 based on the recommendations of the Oil Cost Review Committee, 1984. Under the present system, Oil refineries, marketing companies and pipelines are compensated based on the retention concept and are allowed a return of 12% post tax on net worth. The price of indigenous crude oil is also based on cost plus formula wherein the PSU Oil producing companies are allowed operating cost and 15% post tax return on capital employed.

2. The Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide its order No P-20029/21/94-PP dated January 18, 1995 had appointed a Strategic Planning Group on Restructuring of the Oil Industry ('R' Group) comprising of eminent experts from the Public Sector & Private Sector, distinguished Energy Experts and academicians to make recommendations to meet the policy objectives and initiatives required for restructuring the oil industry. The 'R' Group had recommended the gradual phasing out of APM and introduction of free marketing mechanism. The Government had decided on 1.9.97 to dismantle APM by introducing reforms in a phased manner based on the recommendations of the 'R' Group.

3. The Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide its order No P-20029/21/95-PP dated June 25, 1996 had also appointed an Expert Technical Group to examine the impact on various sectors at different levels of duty structure in case of dismantling of APM. The Expert Technical Group has submitted its report which was under examination of the Government. The report has dealt with phased movement to Market Determined Pricing Mechanism and rationalisation of Custom Tariff & Excise duty rates in respect of dismantling of APM along with its impact on various other sectors.

4. The Government of India has now decided the details of phasing of dismantling programme of administered pricing mechanism and the duty structure for the terminal year i.e. 2001-02, after taking into account the recommendations of Expert Technical Group. The details are given below:

- a) Dismantling of APM in the petroleum sector in phases as per sequence given in Annexure-I starting from 1998-99.
- b) Cost-plus formula is withdrawn for indigenous crude oil producers, the price receivable by oil producers will be increased to international levels in a phased manner by paying a pre-announced increasing percentage of weighted average FOB price of actual imports of crude oil during the transition period.
- c) The system of retention pricing is abolished for all (existing and new) refineries, and pricing of petroleum products at the refinery gate level will move towards import parity, however, Refinery Gate prices of controlled products viz MS, HSD, SKO, LPG and ATF will be fixed at "adjusted import parity" prices for the existing refineries during the transition period, all other products will be sold by the refineries at market driven prices.
- d) Consumer prices of major petroleum products will be moved to market prices, price of HSD will be fixed on the principle of import parity pricing upto ex-storage point level with immediate effect, and prices of other major products, viz. LPG, ATF, SKO and MS, will be moved towards principle of import parity in a phased manner and pricing of Paraffin-Wax, Bitumen, Naphtha, FO and LSHS will be decontrolled.
- e) The transition period will be utilised for servicing and amortising the Oil Bonds worth around Rs.18,200 crores, proposed to be issued by the Government to the Oil companies, the price of crude and petroleum products as mentioned above will be fixed by OCC with enhanced autonomous powers.
- f) Imports and exports of all petroleum products, except crude (slop crude and crude condensate), NGL, ATF, MS and HSD will be decontrolled during the transition period, however, sourcing and import of crude will be allowed to joint and private sector refineries under actual user licensing policy.
- g) Duties on crude and petroleum products will be rationalised in a phased manner.

- h) Investments in the refining sector will be encouraged by providing reasonable tariff protection and making marketing rights for transportation fuels viz MS, HSD and ATF conditional on owning and operating refineries with an investment of at least Rs.2000 crores or oil exploration and production companies producing at least three million tonnes of crude oil annually.
- i) Cost-plus formula for shipping of crude oil is withdrawn and the rates will move towards market related rates.
- j) Freight subsidy on supplies to far-flung areas will be met through the fiscal budget and
- k) Establishment of a regulatory framework to oversee the functioning of and enforcing a competitive framework in the Hydrocarbon Sector.

5. The decisions herein contained will come into force with effect from 1.4.1998 onwards and will remain in force until further orders.

NIRMAL SINGH, Jt. Secy.

#### ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NIRMAL SINGH, Jt. Secy.

**ANNEXURE-I****PHASED PROGRAMME OF REFORMS**

Particulars	Model
<b>Transition Phase</b>	4 years
<b>Year 1 (1998-1999)</b>	
i) Removal of cost plus formula and payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price of actual imports	75 per cent
ii) Products to be controlled during transition period.	MS, HSD, Kerosene, ATF and LPG
iii) Withdrawal of retention margin concept for the refineries and refinery gate prices for controlled products	Adjusted import parity prices to existing refineries and tariff adjusted import parity prices to new refineries.
iv) Products to be decontrolled	Naphtha, FO, LSHS, Bitumen, Paraffin wax
v) Exim Policy	Decanalisation of imports/exports of all petroleum products except crude (slop crude and crude condensate), NGL, ATF, MS and HSD
vi) Sourcing of crude	Sourcing of crude to be liberalised and import to be allowed for joint and private sector refineries under actual user licence
vii) Customs duties	Rationalisation done in a phased manner
viii) Increase in prices of :	
Kerosene (PDS)	30 per cent of existing ex-storage point price
LPG(Domestic)	33 per cent of subsidy passed on.
ix) Freight and other under-recoveries	33 per cent to be passed on, in an equated manner
x) Shipping of crude oil	Withdrawal of cost plus formula for shipping of crude oil and move towards market related rates.

Particulars	Model
<b><u>Year 2 (1999-2000)</u></b>	
i) Payment to crude producers as percentage of weighted average of FOB	77.5 per cent
ii) Increase in prices of :	
Kerosene (PDS)	30 per cent of revised ex-storage point price at the end of year 1
LPG (Domestic)	A further 33 per cent of subsidy to be passed on
iii) Freight and other under-recoveries	A further 33 per cent to be passed on, in an equated manner
iv) Rationalisation of duties	To continue
<b><u>Year 3 (2000-01)</u></b>	
i) Payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price	80 per cent
ii) ATF	Deregulation of imports and pricing
iii) Increase in prices of :	
Kerosene (PDS)	20 per cent of the revised ex-storage point price at the beginning of the year.
LPG (Domestic)	Suitable adjustment in prices to reach subsidy level at 15% of import parity.
iv) Freight and other under-recoveries	Balance subsidy to be passed on, in an equated manner
<b><u>Year 4 (2001-2002)</u></b>	
i) Payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price	82.5%
ii) Increase in prices of:	
Kerosene (PDS)	Suitable adjustment in prices to reach subsidy level at 33.33% of the import parity.
<b><u>2002 onwards</u></b>	Full Deregulation
	Transfer of subsidy on SKO (PDS), LPG(Domestic) and freight subsidy on supplies to far flung areas to the fiscal budget of the Government.

